Title: Need to upgrade the newly opened Kendriya Vidyalayas in Leh and Kargil districts of Ladakh and steps taken by the Government in this regard.

**12.19 hrs.**

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No.13 - Calling Attention. - Shri Chhewang Thupstan.

SHRI CHHEWANG THUPSTAN (LADAKH): Sir, I call the attention of the Minister of Human Resource Development to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "The need to upgrade the newly opened Kendriya Vidyalayas in Leh and Kargil districts of Ladakh and steps taken by the Government in this regard."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI M.A.A. FATMI): Sir, Kendriya Vidyalaya Sangathan is primarily engaged in opening schools to cater to the educational needs of wards of Central Government employees, para-military and Defence sector employees. One KV at Leh (Ladakh) was initially opened in the year 1983-84. At present, this KV is functioning from classes-I to XII in the permanent building with laboratories and other facilities as per norms prescribed for senior secondary school.

Following four additional KVs were opened in the Ladakh keeping in view the difficult terrain of the region:

Zanskar, District Kargil

Kargil, District Kargil

Nubra, District Leh

Chusul, District Leh

.*(Placed in Library See No. LT - 2123/2005)

Though the KVs do not have scheme of mother school in the District Headquarters and branch school with primary sections in the remote location of the district, in the year 2003-04 KVS took a decision to have additional branches of primary sections for KV Leh and KV Nubra at the following places, in view of the terrain:

| MOTHER KV | ADDITION PRIMARY BRANCHES |
|---|---|
| (1) Leh - | (a) Khaltse |
| | (b) Chemdey (Karo) |
| | (c) Saspol/Alchi |
| | Skyur Buchon |
| (2) Nubra - | (a) Panamik |
| | Sumoor |

These primary sections were sanctioned up to Class-III during the year 2004-05. All these branches are at the distance of 70 to 100 kilometres from the mother schools. It was envisaged that the students in the remote places studying in branch schools will have education up to Class-V in the branch school and from Class-VI onwards they will take admission in mother schools.

For the academic year 2005-06, the functioning of these branch schools of KV Leh and KV Nubra, was reviewed and it was found that the facilities provided were not adequate, secondly, enrolment was not exceeding 50 students per branch KV. It was thus decided to keep the branch KVs functional up to Class-III.

The Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary and Higher Education is of the view that these branch schools may continue to operate up to Class V depending upon the local infrastructure available.

**श्री छेवांग थुप्स्तन :** उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे ध्यानार्कृण प्रस्ताव पर जो उत्तर दिया है, मैं उससे पूरी तरह से संतुट हूं। इसके लिये मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी का तहेदिल से शुकिया अदा करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यकारी अधिकारियों ने वे तमाम कदम उठाये हैं जिन्हें पहले डिनाई किया गया था। र्वा 2003-04 के दौरान खोले गये स्कूलों में एडमीशन न मिलने की वजह से कठिन परिस्थिति पैदा हो गई थी लेकिन उसके बाद यहां से इंस्ट्रक्शन्स दी जा चुकी हैं। मुझे ऐसी इत्तला मिली है कि चौथी कक्षा में इनको प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं इस मौके का फायदा उठाते हुये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि लद्दाख क्षेत्र शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा का एक्सपैंशन तो हुआ है लेकिन एजुकेशन में क्वालिटी नहीं आई है। लद्दाख ओटोनॉम्स डेवलेपमेंट कौंसिल कांस्टीट्युट होने के बाद जिला एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये बहुत अच्छा काम कर रहा है। पहली बात का इनीशिएटिव जिसकी देशभर में सराहना की गई है, वह यह है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एन्श्योर किया गया है, स्कूलों के रख-रखाव की जिम्मेदारी पंचायत और कम्युनिटी ने स्वीकार की है। सिलेबस को रेलेवेंट बनाने के लिये लोकल कंडीशन्स और लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुये प्राइमरी लैवल पर सिलेबस में तबदीली लाने के लिये अच्छा कार्य हो रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुये जरूरत इस बात की है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में अच्छी सुविधायें दी जायें क्योंकि लद्दाख के विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन के लिये चंडीगढ़ या श्रीनगर आना पड़ता है। उन्हें वहां बाकी विद्यालयों से कम्पिटीशन करने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए हम लोग चाहते थे कि स्कूल एजूकेशन के साथ-साथ वहां सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजूकेशन के माध्यम से चलने वाली शिक्षा का भी प्रावधान हो। इसी वजह से केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने वहां जो सात-आठ नये स्कूल खोले हैं, उसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत आभारी हूं। इसके साथ ही मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक इन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया है। अभी मंत्री जी ने सिर्फ यही कहा है कि पांचवी कक्षा तक उन्हें चलाने का प्रिंसिपल उन्होंने स्वीकार कर लिया है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो दूर-दराज के पांचवी कक्षा तक के स्कूल हैं, आप उन्हें रेगुलराइज कर दें। उन्हें जमीन दे दी गई है। लेकिन जब तक उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से फंड मुहैया नहीं होता है, तब तक हम लोग वहां कक्षा चलाने तथा अध्यापकों के रहने की व्यवस्था अपने स्तर पर करने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय का जो मदर स्कूल वहां है, वह 12वीं कक्षा तक चल रहा है। चूंकि अब सात-आठ फीडर स्कूल पूरे लद्दाख क्षेत्र में बन जायेंगे तो छठी कक्षा के बाद उन्हें लेह मदर स्कूल में आना पड़ेगा, इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि उसे धीरे-धीरे रेसिडेन्शियल स्कूल बना दिया जाए। इसके लिए बेशक वहां जो खर्चा होगा, वह आप स्टूडैन्ट्स से वसूल करे, उनके लिए फ्री रेसिडेन्शियल व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें वहां सिर्फ फैसिलिटी दे दें और उसका पैसा विद्यार्थियों से चार्ज करें। इसके लिए सारे पेरेन्ट्स और हम लोग तैयार हैं। मैं एक बार फिर से भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** शैलेन्द्र जी, आप क्लेरिफिकेशन क्वैश्चन पूछ सकते हैं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज शिक्षा के बारे में चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, सभी चिंतित हैं। हमारे लद्दाख और लेह के माननीय साथी ने अपने यहां केन्द्रीय स्कूल के उन्नयन की आवश्यकता के बारे में अपनी बात यहीं रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अंतरराट्रीय स्तर के सिलेबस और पाठ्यक्रम की जरूरत है। क्या मंत्री जी इसका प्रावधान करेंगे।

दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि ज्यादातर केन्द्रीय विद्यालय शहरों में स्थित हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोई स्कूल नहीं है। क्या मंत्री जी पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने की व्यवस्था करेंगे?

**श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी :** उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने सिलेबस के बारे में कहा, केन्द्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय का सिलेबस किसी भी लिहाज से अंतरराट्रीय स्तर से कम नहीं है और मैं समझता हूं कि सी.बी.एस.ई. का बहुत अच्छा सिलेबस इन दोनों विद्यालयों में चलता है। जहां तक इन्होंने कहा कि केन्द्रीय विद्यालयों को ब्लाक लैवल पर खोलने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे ऐसे जिले हैं, जहां पर कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं खुल सका है। हमारा टारगेट यही है कि पहले हम सारे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय पहुंचा दें और इस टारगेट को हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। इस र्वा भी हम लोग कुछ केन्द्रीय विद्यालय खोल रहे हैं। उसमें यही टारगेट रखा गया है कि पहले उन जिलों को टच किया जाए, जहां एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। जब और नम्बर्स हमें मिलेंगे तो उसके बाद हम लोग प्रखंड स्तर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा।

हमारे साथी ने कारगिल और लेह के बारे में सवाल किया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कारगिल और लेह की पूरी आबादी तकरीबन ढाई लाख है। जैसा अभी बताया गया है कि उसके अंदर छः एडिशनल ब्रांचेज प्राइमरी लैवल पर हम लोग चला रहे हैं, जो और कहीं नहीं है। वह एक खास कंडीशन में, खास वजह के कारण चल रहे हैं। क्योंकि वहां के हालात जरा मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा जो लोकल स्कूल जिस लैवल पर होने चाहिए, वहां नहीं हैं। इसकी वजह से हम लोगों को वहां खास तौर से प्राइमरी सैक्शन का स्कूल चलाना पड़ रहा है। वहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं हैं। हम लोगों ने मांगा है कि हमें रूम दें, ताकि चौथी और पांचवी की क्लासेज वहां चल सकें। अगर हमें वहां जमीन उपलब्ध हो जाए तो हम लोग बिल्डिंग बना लेते।

अभी तक ज़मीन भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। एक बार सरकारी तौर पर ज़मीन उपलब्ध हो जाए तो फिरे हम उसमें क्लासरूम बना देंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या हर ब्लाक में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलेंगे?

**श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कारगिल और लेह की बात कर रहा था। ब्लाक स्तर पर खोलने का तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता है जब तक पूरे देश में हर जिले में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय नहीं बना दें। जब वह बन जाएंगे और उसके बाद यदि एक्सटैंशन होगा तो हम ब्लाक स्तर पर भी केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसका मौका तब तक नहीं आएगा जब तक हर जिला मुख्यालय में एक स्कूल न खोल दें।

**श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) :** उपाध्यक्ष जी, कहीं कहीं एक जिले में दो लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसलिए हमारी मांग है कि एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में भी कम से कम एक स्कूल खोलने की आवश्यकता है। इस संबंध में मंत्री महोदय बताएं।

**श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी :** उपाध्यक्ष जी, जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सवाल है, जैसा कि मैंने अपने स्टेटमैंट में कहा कि केन्द्रीय विद्यालयों के खोले जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों, पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ और डिफैन्स सैक्टर के कर्मचारियों के बच्चे इसमें पढ़ाई कर सकें और ज्यादातर ऐसे लोग डिस्ट्रिक हैडक्वार्टर में ही रहते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट में दो पार्लियामैंट्री कांस्टीट्यूएंसी होती हैं, तो फिर वही बात आती है कि प्रखंड स्तर पर केन्द्रीय विद्यालय खोलेंगे या नहीं। पहले हम जिला मुख्यालयों में खोलेंगे। अभी तक जितना हमने देखा है, एक एक जिले के अंदर कहीं-कहीं कई केन्द्रीय विद्यालय हैं, लेकिन खासी तादाद में ऐसे जिले हैं जहां पर अभी तक एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है। यूपीए सरकार का मानना है कि कम से कम एक एक केन्द्रीय विद्यालय हर जिले में खुले। पहले फेज़ में उसको खोलेंगे, उसके बाद आपकी मांग पर निगाह डालेंगे।

**श्री राम कृपाल यादव (पटना) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने का क्या क्राइटीरिया आपने अपनाया है? दूसरी बात यह है कि आपके उत्तर से यह पता चलता है कि अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां केन्द्रीय विद्यालयों की आवश्यकता है मगर उस आवश्यकता के अनुसार आपने ये विद्यालय नहीं खोले हैं। बिहार प्रदेश पिछड़ा इलाका है, गरीब और फटेहाल है। वहां ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां आपने केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोले हैं।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि केन्द्रीय विद्यालय तो खोल देते हैं और देश के आम लोग, गरीब लोग उसमें पढ़ना चाहते हैं तो उसमें दाखिला लेने के लिए प्र ाथमिकता का जो क्राइटीरिया आपने रखा है, उसमें किसान के बच्चे, गरीब तबके के बच्चे दाखिला नहीं ले पाते हैं। वे उस क्राइटीरिया में आते ही नहीं हैं। आपने कहा है कि डिफैन्स में काम करने वाले और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को प्राथमिकता पर लेंगे। इस प्रकार उसमें सात-आठ क्राइटीरिया हैं। मगर ऐसे अवाम हैं जो उनके अंतर्गत नहीं आते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आम लोगों की भावनाओं को देखते हुए जो गरीब, पिछड़े, किसान, मज़दूर अपने बच्चों को केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आप नियमों को वेव ऑफ करेंगे जिससे वे अपने बच्चों को उन विद्यालयों में पढ़ा सकें?

**श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी :** उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्राइटीरिया पहले से ही फिक्स है कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट इंप्लॉइज़, पैरा मिलिट्री फोर्सेज़ के लोग और जो स्टेट गवर्नमैंट में काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। जहां उनकी संख्या ज्यादा होती है, वहीं पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाते हैं। जब सीट्स बच जाती हैं तो वह सभी के लिए एवलेबल होती हैं, उसमें हम लोग फर्क नहीं करते हैं और उसमें सबको एडमिशन देते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि बिहार में कुछ जिले ऐसे हैं जहां विद्यालय नहीं खोले हैं। मैं उनको और सदन को आश्वसान देता हूं कि ऐसे जिले जहां पर केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, उनको प्राथमिकता देकर वहां पर केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे।

**श्री राम कृपाल यादव :** मेरी बात का पूरा जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा था कि क्राइटीरिया क्या है। â€¦ (व्यवधान) आम लोगों के लिए अगर उन स्कूलों को नहीं चलाना है तो क्या फायदा है?â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up matters of urgent public importance to be raised after Question Hour.